reported statement of the Prime Minister of Pakistan that it would not be possible for Pakisan to prevent in future, the J.K.L.F. marches from crossing the lines of Actual Control in Jammu and Kashmir and that India should agree for expeditious implementation of the U. N. Resolution on Kashmir;

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto; and

(c) what preventive steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) Government are aware of press reports in this regard.

(b) Government have urged the Government of Pakistan to take effective steps to prevent any violations of the LOC|border and to honour its bilateral obligations in terms of the Simla Agreement.

(c) Adequate measures exist to ensure the inviolability of the LOC and our borders at all times.

इराक द्वारा तेल विनिमय के प्रस्ताव को पुनः प्रचलन में लाना

1641. **श्री राम जेठमलानी**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1992 के "इकानामिक टाइम्स" में "इराक रिवाइव्स आयल बारटर प्रोपोजल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इराक द्वारा दिसम्बर 1991 तक भारतीय कम्पनियों को कुल कितनी देनदारी की राशि थी ;

(ग) क्या इराक तेल की आपूर्ति कर इस देनदारी का भुगतान करने का इच्छुक है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को शीघ्र निपटाने और देश में अपरिष्कृत तेल की कमी को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से इराक पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ढील देने के लिए आग्रह किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह आग्रह कब किया गया था और उस पर इराक की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां ।

(ख) 30 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार सम्बद्ध राशि 614.52 मिलियन अमरीकी डालर है ।

(ग) से (ङ) इराक की सरकार ने समय-समय पर अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि वह भारतीय कम्पनियों को देय अपने ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में तेल की आपूर्ति करने को तैयार है, बशर्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रतिबन्ध समिति इराक को इस प्रयोजनार्थ तेल के निर्यात की अनुमति दे । संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के माध्यम बसे यह मामला प्रतिबन्धसमिति के साथ उठाया था परन्तु समिति ने प्रस्तावित व्यवस्था को अपना अनुमोदन नहीं दिया है ।

New Draft Treaty with Russia

1642. SHRI M. S. GURUPADASWAMY:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Russia has offered a new draft treaty in substitution of the earlier Indo-Soviet agreement for friendly relationship;

(b) if so, what are the details thereof stating the spheres in which the